भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2242
बुधवार, 09 अगस्त, 2023/ श्रावण 18,1945(शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण

2242 # डा. सुमेर सिंह सोलंकी :

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) देश में अब तक कितनी सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग) : देश भर में 63,000 कार्यात्मक पैक्स/वृहद क्षेत्र बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (लैम्प्स)/कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। 28 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 60,685 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए; जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के 4,534 पैक्स शामिल हैं; स्वीकृत कर दिए गए है।

यह परियोजना पैक्स को विभिन्न लाभ प्रदान करेगी जैसे कि उनके संचालन की दक्षता में वृद्धि, ऋण का त्वरित वितरण सुनिश्चित करना, लेनदेन लागत को कम करना, भुगतान में असंतुलन को कम करना, DCCBs और StCBs के साथ निर्बाध लेखांकन और पारदर्शिता बढ़ाना। यह किसानों के बीच पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता भी बढ़ाएगी । इस परियोजना के लिए सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है।हार्डवेयर खरीद, सिस्टम इंटीग्रेटर को ऑनबोर्डिंग और राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

*****